06

ISSN - 0973-1628

158

Since 2002

Issue - 158, Vol-XVI (3), May - 2017
www.researchlink.co

Mob. 94252-11987
डॉ.प्रमोद यादव
10 / 27, शिक्षक नगर
दुर्ग (छत्तीसगढ़) - 491001
दुर्ग (छत्तीसगढ़)
596/158 W

Microsoft

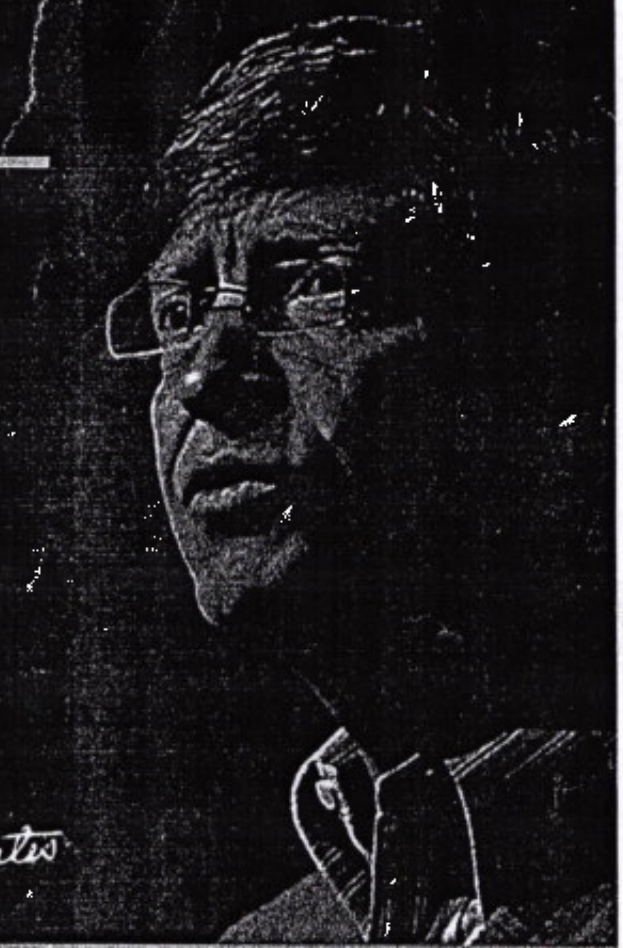

When you have money in hand,
only you forget who are you.
But
When you do not have
any money in your hand,
the whole world forget
who you are
It's Life.....

Bill Gates

An International Registered and Referred Monthly Journal

RESEARCH Link

Impact Factor 2.782 2015

Kala, Samaj Vigyan awam Vanijya

250/-

:: CIRCULATION ::

Andaman-Nicobar / Bihar / Chattisgarh / Delhi / Goa / Gujarat / Haryana / Himachal / Jammu & Kashmir / Karnataka /

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College

Seth R.C.S. ... College ... Chhattisgarh

- भारत में गठबंधन सरकार का स्वरुप एवं उसके परिणामों का राजनीतिक विश्लेषण
  डॉ.प्रमोद यादव एवं डॉ.अलका मेश्राम (596)........................82
- भारतीय प्रजातंत्र में जन कल्याण हेतु - जवाबदेह प्रशासन
  आरती तिवारी (589)........................85
- छत्तीसगढ़ के पंचायती राज में अनुसूचित जाति के नेतृत्व की दशा और दिशा
  डॉ.प्रियंका वैष्णव एवं डॉ.डी.एन.सूर्यवंशी (611)........................87
- संसदीय व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका
  भूपेन्द्र कुमार एवं डॉ.आर.के.पुरोहित (604)........................89
- उत्तर-पूर्व भारत में आतंकवाद : समस्याएँ एवं समाधान
  डॉ.आर.एस.चंदेल (607)........................91

Tourism

- Unexplored Forts of Central India
  Dr Harkirat Bains (H)........................93

Education

- Multiple Intelligence
  Dr.Usha Rao (531)........................96
- माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की अंक गणितीय कमजोरियों की पहचान एवं उसका निदान
  संतोष कुमार शर्मा, डॉ.नीरा पाण्डेय एवं डॉ.पुष्पलता शर्मा (578)..99

Law

- Fundamental Rights, Duties and Human Rights of Person under Constitution of India
  Meenu D. Sharma (601)........................102
- Sexual Harassment of Women at Workplace in India : Constitutional & Legal Remedies
  Dr. Saptmuni Dwivedi (580)........................105

Commerce

- Food Security and Public Distribution System in India : Problems and Prospects (Special Reference to Dist. Raisen (M.P.)
  Mrs. Chhaya Sharma & Dr. Bharat Sing Goyal (576)..108
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) : एक समीक्षा एवं इनपुट सेवा वितरण की अवधारणा
  डॉ.विजय अग्रवाल एवं श्रीमती सीमा अग्रवाल (586)........111

Home Science

- Food Synergy : Importance and Awearness
  Rupali Srivastava & Dr. Sarita Verma (590(2))........114

Research Paper

- Adultery : Historical Perspective
  Dr.Sangeeta Thakur (573)........................116
- A Study on the school life of the students of Pota Cabins in Dantewada District of Chhattisgarh State
  Dr. Divya Sharma (586)........................119
- Demonetization in India : Impact Towards Various Sector of Societies
  Pallavi Saxena (606)........................123
- फिर उलझा चक्रव्यूह में मणिपुर
  डॉ.आर.एस.चंदेल (607)........................125
- माध्यमिक स्तर पर पर्यावरण सम्बंधी जागरुकता का अध्ययन
  दिनेश कुमार छड़ावदिया (512)........................128
- ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक, व्यावसायिक एवं राजनीतिक स्थिति
  चन्द्रमोहिनी एवं डॉ.हेमलता संगुरी (590(1))........................130
- राष्ट्रीय एकता में सूफी संतों का योगदान
  डॉ.प्रीति श्रीवास्तव (524)........................131
- पॉलीथीन के प्रयोग से उत्पन्न समस्या व समाधान
  श्रीमती रीना ताम्रकार एवं डॉ.मोनीया राकेश सिंह (600)......132

- शोधपत्र भेजने संबंधी नियम........................25, 127
- रिसर्च लिंक सदस्यता फॉर्म........................134

❖❖

साहित्य, संस्कृति एवं सृजन
विशेष खण्ड के लिए रचनाएँ आमंत्रित

साहित्य, संस्कृति और सृजन से सम्बन्धित सामग्री विशेष खण्ड के तहत पिछले कई समय से दी जाती रही है। शोधार्थियों, प्राध्यापकों के साथ ही इससे समकालीन सृजनधर्मी लगातार जुड़ रहे हैं। इसके लिए हम बहुत हृदय से समकालीन तेवर की धारधार सामग्री सादर आमंत्रित करते हैं।

इस विशेष खण्ड के लिए जो सामग्री भेजी जाए, वह कृतिदेव 010 फोंट में एम.एस.वर्ड या पेजमेकर 6.5 में टाईप की गई हो। मूल टाईप की गई फाईल की सॉफ्टकॉपी के साथ-साथ उसकी पीडीएफ भी भेजी जाए। नई पुस्तकें, साहित्यिक आयोजनों की संक्षिप्त रपट (फोटो सहित) भेजी जा सकती है।

लेखक का संक्षिप्त रचनात्मक परिचय, फोटो तथा पत्र-व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर सहित हमारे ईमेल आई.डी. researchlink@yahoo.co.in पर प्रेषित करें। विशेष खण्ड की सामग्री को हमारी वेबसाइट researchlink.co पर भी देखा व निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

बेहतर होगा, सीधे इस नंबर पर सम्पर्क करें -

099264-97611

रिसर्च लिंक की सदस्यता का शुल्क भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सीधे इसमें या जमा किया जा सकता है। बैंक का विवरण निम्नानुसार है -
बैंक : स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, ब्रांच : ओल्ड पलासिया, इन्दौर, कोड - SBIN 000 3432 खाते का नाम : रिसर्च लिंक
खाता नंबर : 63025612815
भुगतान की मूल रसीद, शोध पत्र एवं सीडी के साथ कार्यालयीन पते पर भेजना अनिवार्य है।

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College Durg (C.G.)

Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

Since March 2002
An International Registered & Refereed Monthly Journal
Political Science
Research Link - 158 Vol - XVI (3) May - 2017 Page No. 82-84
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

भारत में गठबंधन सरकार का स्वरुप एवं उसके परिणामों का राजनीतिक विश्लेषण

प्रस्तुत शोधपत्र में भारत में गठबंधन सरकार का स्वरुप एवं उसके परिणामों का राजनीतिक विश्लेषण किया गया है। देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, जिसमें किसी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण समझौते की राजनीति का जन्म हुआ। केन्द्र के स्तर पर पहली बार 1977 में मिली-जुली सरकार का निर्माण हुआ। गठबंधन की सरकार यदि 5 वर्ष पूर्ण कर देश को प्रति के पथ पर ले जाती है, तो यह संकेत है कि भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति का युग प्रारंभ हो चुका है। 2014 में सम्पन्न 16वीं लोकसभा चुनाव के परिणामों ने इस पुराने मिथक को तोड़कर राजनीति के नये समीकरण के बारे में सोचने के लिए देश के बौद्धिक वर्ग को मजबूर कर दिया है।

डॉ.प्रमोद यादव* एवं डॉ.अलका मेश्राम**

प्रस्तावना :

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा केन्द्रीय और राज्य स्तर पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे संविधान में चुनाव से पहले या बाद में गठबंधन बनाने के संदर्भ में कोई दिशा–निर्देश नहीं दिए गए हैं। नतीजन इस तरह के गठजोड़ से सरकार गठन के मौके पर और उसके बाद भी अनैतिक सौदेबाजियों का रास्ता खुलता है। भारत में गठबंधन की राजनीति इसलिए अस्तित्व में आई है कि भारतीय लोकतंत्र का मिजाज भी गठबंधनवादी है। देश की बहुलतावादी संस्कृति और विविधतावादी पहचान गठबंधन की राजनीति के तहत ही इसके लोकतंत्र में पूरी तरह परिलक्षित होती है। गठबंधन के चलते कई बार सरकार में अनिर्णय और अस्थिरता की स्थिति बनती है। अतः चुनाव पूर्व या पश्चात् राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन के बारे में विस्तारित नियम–कायदे निर्धारित किए जाने चाहिए।

अध्ययन के उद्देश्य : विगत कई वर्षों के चुनाव परिणाम यह साबित करते हैं कि भारत में गठबंधन की राजनीति सिर्फ सतही नहीं, बल्कि इसकी जड़ें गहराई तक जा चुकी है। ये भारतीय राजनीति की दशा और स्वरूप को भी प्रभावित कर सकती है। इस शोध–पत्र के माध्यम से भारत में गठबंधन सरकार का स्वरूप एवं उसके परिणामों का एक राजनीतिक विश्लेषण कर यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि इस गठबंधन से देश की दिशा एवं दशा किस प्रकार प्रभावित होती है।

गठबंधन की पृष्ठभूमि : भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है कि यहाँ लोकतंत्र है। नेता हैं और राजनीतिक दल भी हैं, किन्तु विचारधारा का स्तंभ कमजोर होता जा रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे प्रमुख राजनीतिक दल हों, या स्वयं को समाजवादी आन्दोलन का पर्याय मानने वाले दल। साम्यवादी विचारधारा के पैरोकार बने साम्यवादी दल हों, या विशुद्ध रूप से समाज में अगड़े–पिछड़े वर्गों में राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी हो। सत्ता तक पहुँच बनाने या सत्ता में बने रहने के लिए सभी दल अपनी विचारधारा को किनारे करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। इन दलों के साथ जुड़े नेताओं का एक वर्ग ऐसा भी है, जिनके लिए विचारधारा तो क्या, दल भी कोई मायने नहीं रखता। वर्तमान समय में हो रहे लोकसभा या विधानसभा चुनावों में यह बात एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, जिसमें किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण समझौते की राजनीति का जन्म हुआ है।

गठबंधन की आवश्यकता : गठबंधन विभिन्न राजनीतिक दलों का किसी विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी सहमिलन है। विभिन्न दलों या राजनीतिक विचारधारा या पहचान रखने वाले समूहों के बीच आपसी समझौता गठबंधन कहलाता है। जब सदन में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो सदन में आवश्यक बहुमत जुटाने के लिए दो या अधिक दलों के बीच आपसी समझौते से गठबंधन सरकार का जन्म होता है। ये गठबंधन चुनाव पूर्व या आम चुनाव के बाद हो सकता है। इस प्रकार गठबंधन तीन प्रकार का हो सकता है :

(1) किसी एक विचारधारा से संबद्ध दल समूह मिलकर चुनाव लड़े और सरकार गठित करे, जैसा कि केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा तथा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में साम्यवादी दल समूह द्वारा होता है।

(2) जब चुनाव के पूर्व अलग–अलग राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी संभावनाओं के आधार पर गठजोड़ बनाकर चुनाव लड़ा जाए और वे संयुक्त रूप से विजयी हों, जैसा कि 1977 में जनता

*सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान विभाग), सेठ आरसीएस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
**प्राचार्य, शासकीय नेहरु स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़ (छत्तीसगढ़)

Seth R.C.S. Arts & Commerce College DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)

पार्टी और 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में हुआ था।

(3) किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राजनीतिक दल चुनाव के पश्चात् गठबंधन करे और सरकार बनाए। 1989 में गठित राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार तथा 2004 में गठित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार इसका उदाहरण है।

राज्यों में गठबंधन सरकार की अवधारणा नई नहीं है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुए चुनावों में मुम्बई, असम तथा उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में गठबंधन दलों की सरकारें बनी थी। उत्तरप्रदेश में अभी हाल में सम्पन्न 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने चुनाव पूर्व गठबंधन एवं सीटों का बँटवारा कर चुनाव लड़ा था, परन्तु ये गठबंधन सत्ता प्राप्त नहीं करे सका।

तालिका 1 से यह स्पष्ट लगता है कि भारत में गठबंधन सरकारों का ही युग है। 16 वीं लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में सम्पन्न हुए। 16 मई 2014 को चुनाव निर्णय घोषित हुए, जिसमें भाजपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। भाजपा ने चुनाव में 543 सीटों में से 282 पर जीत दर्ज की है और 30 वर्षों के बाद किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत मिला है।

गठबंधन का राजनीतिक व्यवस्था में प्रभाव : गठबंधन की राजनीति मजबूत लोकतंत्र का प्रतीक नहीं, बल्कि लोकतंत्रीय मजबूरी है, क्योंकि इसमें स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के स्थान पर "शह-मात और घात" की रणनीति में कार्य किया जाता है तथा संसदीय लोकतंत्र में गठबंधन एक परिस्थितिजन्य व्यवस्था है। कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता है कि उसे गठबंधन की सरकारों का संचालन करना पड़े। राजनीति की यह बड़ी विडम्बना है कि जो सबसे बड़ा साझेदार है, वह विवश रहता है। उसके ऊपर छोटे घटकों का दबाव रहता है। पूर्व के वर्षों में जिस गठबंधन की सरकारों ने सत्ता का संचालन किया है, उनके विश्लेषण से यह आँकलन किया जा सकता है कि यदि गठबंधन का मजबूत नेतृत्व है तो वह सफलतापूर्वक सत्ता का संचालन कर पाता है। वहीं गठबंधन के कमजोर नेतृत्व से विकास के सारे मार्ग अवरूद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सारी शक्ति केवल गठबंधन को बनाए रखने में ही रह जाती है।

राजनीतिक दलों का यह गठबंधन सरकारों के निर्माण व उसकी रक्षा के लिए होता है। गठबंधन सरकार की मतभेदों के बावजूद एक समवेत स्वर होती है। इसका राजनीतिक व्यवस्था पर निम्नानुसार प्रभाव पड़ता है :

(1) गठबंधन सरकार यद्यपि ऊपर से ठोस प्रतीत होती है तथापि प्रत्येक राजनीतिक दल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। अतः भीतर मतभेद के स्वर विद्यमान रहते हैं।

(2) यदि यह गठबंधन चुनाव के पूर्व होता है, तो इसका लक्ष्य चुनाव में बहुमत प्राप्त कर सरकार का गठन करना होता है। इसमें अवसरवादिता का तत्व कम होता है और गठबंधन साथ-साथ काम करने का आधार बन जाता है किन्तु यही गठबंधन चुनाव के बाद होता है, तो उसमें अवसरवादिता का तत्व अधिक अंशों में विद्यमान होता है, जो गठबंधन को कमजोर कर देती है।

(3) गठबंधन सरकार में भागीदार दल समान विचारधारा के नहीं होते हैं न ही समानधर्मी होते हैं। अतः एक सुदृढ़ इकाई नहीं बन पाते हैं।

(4) राज्यों में गठबंधन सरकार का जन्म बार-बार दल बदल से होता है। इसीलिए इसमें गम्भीरता का अभाव दिखता है और यह प्रवृत्ति ही सरकार की असफलता और अंत का कारण बन जाती है।

(5) गठबंधन सरकार में प्रत्येक राजनीतिक दल अपने निहित स्वार्थों की रक्षा और पूर्ति में रत रहता है। अतः

तालिका 1 : भारत में गठबंधन सरकारों का कार्यकाल

क्र	नेतृत्व (नेता)	शपथ	अवसर	कुल दिवस	समर्थन
1.	श्री मोरारजी देसाई (जनता पार्टी)	24 मार्च 1977 (छठीं लोकसभा)	1	856	संगठन कांग्रेस / जनसंघ / भालोद / संयुक्त समाजवादी दल / कांग्रेस फोर डेमोक्रेसी
2.	चौधरी चरण सिंह (जनता-एस)	28 जुलाई 1979 (छठीं लोकसभा)	1	170	कांग्रेस का बाहरी समर्थन
3.	श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह (राष्ट्रीय मोर्चा)	02 सितम्बर 1989 (नवीं लोकसभा)	1	343	वामपंथी दलों का संयुक्त मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का बाहरी समर्थन
4.	श्री चन्द्रशेखर (जनता एस)	10 नवम्बर (नवीं लोकसभा)	1	223	कांग्रेस का बाहरी समर्थन
5.	श्री अटलबिहारी बाजपेयी (भाजपा)	16 मई 1996 (ग्यारहवीं लोकसभा)	1	16	शिवसेना / अकाली दल / हरियाणा विकास पार्टी
6.	श्री एच.डी.देवगौड़ा (जनता दल)	1 जून 1996 (ग्यारहवीं लोकसभा)	1	324	संयुक्त मोर्चा / जनता दल / तेलगूदेशम / असम गणपरिषद / कांग्रेस (एस) द्रमुक / कांगेस का बाहरी समर्थन
7.	श्री अटलबिहारी बाजपेयी (भाजपा)	19 मार्च 1998 (बारहवीं लोकसभा)	2	413	18 दलों का गठबंधन तृणमूल कांग्रेस, तेलगूदेशम और राष्ट्रीय लोकदल का बाहरी समर्थन
8.	श्री अटलबिहारी बाजपेयी (भाजपा)	13 नवम्बर 1999 (तेरहवीं लोकसभा)	3	1512	24 दलों का का गठबंधन (एनडीए)
9.	डॉ.मनमोहन सिंह (कांग्रेस)	22 मई 2004 (चौदहवीं लोकसभा)	1	1825	यू.पी.ए.वामपंथी दलों का बाहरी समर्थन
10.	डॉ.मनमोहन सिंह (कांग्रेस)	22 मई 2009	2	1620	कांग्रेस एवं अन्य दल
11.	श्री नरेन्द्र मोदी	26 मई 2014 सोलहवीं लोकसभा			एनडीए

Seth R.C.S. Arts & Comm. College DURG Chhattisgarh
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm.
College Durg (C.G.)

वैमनस्य और तनाव की संभावनाएँ बढ़ जाती है।

गठबंधन का सकारात्मक पक्ष : सरकार विकास के लिए आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि वर्ष 1990 में आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका और यूरोप में कई देशों की वित्तीय अर्थव्यवस्था मंदा हो चुकी थी। इसका मुख्य कारण उदारीकरण और खुले बाजार की नीति रही। भारत में वैश्विक मंदी की आँच बहुत अधिक नहीं आई। गठबंधन सरकार की उदारीकरण की नीतियों का सहयोगी दलों ने समर्थन प्रदान किया। भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय संकट के कालचक्र में नहीं फँसने का मूल कारण गठबंधन का सरकार ही थी। एक दल का शासन होने पर किसी भी नीति को लागू करने का सरकार में अंतर्द्वंद नहीं होता, गठबंधन सरकार होने की वजह से सभी सहयोगी पार्टियों से विचार–विमर्श कर फैसले लिए जाते हैं। अर्थात् गठबंनधन सरकारें एकाधिकारी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाती है। गठबंधन सरकारें जहाँ पूर्ण समन्वय व देशहित को ध्यान में रखकर चली है, वह सफल रही है। ऐसी सरकारों ने कई महत्वपूर्ण कार्य देशहित में किए हैं।

गठबंधन का नकारात्मक पक्ष : गठबंधन सरकार के कार्यकाल में स्थिरता न होने से विकास प्रभावित होता है। इसका असर कई बार निवेश पर भी पड़ता है। ऐसी सरकार से न केवल आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और समसायिक विकास भी प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण सहयोगी क्षेत्रीय पार्टियों के अपने–अपने मुद्दे होते हैं। उनके राजनैतिक एजेण्डे और सोच में अंतर होता है, जिसके कारण उनमें टकराव होना लाजमी है। वे अपने–अपने मुद्दों को लेकर खींचतान में लगे रहते हैं, उनको जनता का हित कम और अपना हित अधिक नजर आता है। इससे संसदीय प्रणाली का पालन कठिन हो जाता है। गठबंधन सरकार से आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे हमेशा राजनैतिक अस्थिरता का माहौल बना रहता है। कारोबार को सही दिशा नहीं मिल पाती क्योंकि कारोबारियों को विश्वास नहीं होता है कि सरकार कब तक चलने वाली है, आर्थिक तंगी के दौर में ढुलमुली सरकार विकास की गति को धीमी कर देती है। जब किसी भी गठबंधन में व्यक्तिगत स्वार्थ एवं महत्वाकांक्षाएँ विभिन्न दलों में आ जाती है, तो गठबंधन सरकारें विफल हो जाती है।

गठबंधन की सफलता हेतु सुझाव :

(1) गठबंधन में किसी एक दल की तानाशाही न हो। सभी दलों को समान महत्व दिया जायें।

(2) सभी घटक दलों में तालमेल होना चाहिए। सभी निर्णय सभी दलों को संयुक्त लेनी चाहिए तथा सहअस्तित्व एवं सहयोग की भावना होनी चाहिए।

(3) गठबंधन का निर्माण तमाम साझेदार पार्टियों द्वारा संयुक्त लिखित करार के रूप में होना चाहिए, जिसे राष्ट्रपति / राज्यपाल को आधिकारिक तौर पर सौंपा व सत्यापित कराया जाए।

(4) इस गठबंधन के नियोजित कार्य के अधीन कुछ मामलों में खिलाफ वोट करने वाले तमाम साझेदार सदस्यों व गठबंधन सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय सदस्यों के भी स्वतः रद्द होने का प्रावधान हो। गठबंधन को बाहर से समर्थन देने वाले पार्टियों के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

(5) गठबंधन सरकार को भीतर अथवा बाहर से समर्थन देने वाले एक तिहाई सदस्य (निर्दलीय सदस्यों समेत) यदि राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रपति / राज्यपाल को पहले से सूचित कर सरकार के खिलाफ जाने का फैसला करते हैं, तो इन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए।

(6) गठबंधन सरकार में निरंकुश प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि गठबंधन के साझेदार जहाँ पर जरूरी हो, वहाँ विरोध भी जता सके।

(7) सत्ताधारी गठबंधन को समर्थन देने वाले निर्दलीय सांसदों, विधायकों की स्थिति के साथ उनके दायित्वों का भी स्पष्ट निर्धारण जरूरी है।

(8) एक जवाबदेह गठबंधन सरकार बनाने के क्रम में समर्थन देने वाले सभी निर्दलीय सांसद या विधायक इसके बारे में एक लिखित करार करें, जिसकी एक प्रति राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपी जाये। इससे मुद्दों पर आधारित समर्थन या न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार की स्थिरता हासिल करने का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा।

निष्कर्ष :

अतः आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दलों की मान्यता के नियम बदले जाएं। कुल डाले गये 30 प्रतिशत मतदान प्राप्त न करने वाले दलों की न केवल मान्यता समाप्त किया जाए, बल्कि उससे चुनाव खर्च भी वसूला जाए। भारत में गठबंधन सरकार के अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि गठबंधन की सफलता उसमें शामिल घटक दलों के आचरण पर निर्भर करता है। इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए विवादास्पद मुद्दों को दरकिनार करना आवश्यक हो जाता है। घटक दलों का एकमात्र लक्ष्य सत्ता में भागीदारी न होकर शासन में गुणवत्ता सुनिश्चित करना होना चाहिए। क्षेत्रीय समस्याओं का उचित समाधान निकाला जाना आवश्यक है, पर उसे राष्ट्रहित से ऊपर नहीं रख जा सकता। ऐसी सरकार में सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार में दलों को लोकसभा में उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। समग्र दृष्टि से आज गठबंधन की सरकार बनाने से पहले अपने राजनीतिक मूल्यों को अनिवार्यता प्रदान करना आवश्यक है, जिससे देश की जनता का विश्वास राजनीति के प्रति स्थिर रहे और राष्ट्र विकास में सहभागी बनें। इससे ही गठबंधन सरकारों को सफल बनाया जा सकेगा।

<u>संदर्भ</u> :

(1) रिसर्च जर्नल ऑफ सोशल एण्ड लाइफ साईसेस, अंक 18–1, गायत्री पब्लिकेशन्स, रीवां, वर्ष जून 2014, पृ. 137. (2) इन्दा, उम्मेद सिंह (2010) : संसदीय व्यवस्था में परिवर्तन की दिशा, कल्पज पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ. 96. (3) भल्ला, आर.पी. (2014) : इलेक्शन इन इंडिया, प्रगति प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 80. (4) गोस्वामी, भालचंद (2016) : भारत में चुनाव सुधार दशा और दिशा, पोइन्टर पब्लिकेशन, जयपुर पृ. 143. (5) इलेक्टोरल रिफार्म ब्रेक ऑफ पोलिटिक्स बिल, रामकृष्ण विकास पब्लिकेशन, नई दिल्ली, वर्ष 2015, पृ. 209.

❀❀

Principal